भारत में कमजोर आधारभूत संरचना और नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन

डॉ. विनीत कुमार तिवारी
असिस्टेंट प्रोफेसर
श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय दादर आश्रम सिकंदरपुर बलिया

शोध सार

भारत में कमजोर आधारभूत संरचना (भौतिक और डिजिटल दोनों) ने नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बाधाएं खड़ी कर दी हैं। सार्वजनिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों की आंखों में साफ नहीं दिखने वाली लैब सुविधाएं, पर्याप्त स्टाफ की कमी और आद्योपचारिक संसाधनों की अनुपलब्धता NEP की बहुविषयक शिक्षा, प्रयोगशाला-आधारित सीखने और स्कूल क्लस्टर मॉडल जैसे नवाचारों को जमीन पर उतारने में रोड़ा बन रहे हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के कई उच्च शिक्षा संस्थानों में "सही इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होने" के कारण विज्ञान, मीडिया लैब और खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही, और लगातार अधिकतम लघु-श्रेणी के अथवा अतिथि संकायों पर निर्भरता बनी हुई है । डिजिटल अवसंरचना की बात करें तो, NEP की डिजिटल योजनाएं जैसे DIKSHA, NDEAR और ICT क्लासरूम ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में पहुंचने में असफल साबित हुई हैं, क्योंकि व्यापक डिजिटल विभाजन (digital divide) आज भी बना हुआ है—यूडीआईएसई+ के आंकड़ों के अनुसार, अधिकांश सरकारी स्कूलों के पास कार्यशील कंप्यूटर और इंटरनेट की कमी है । भारतनेट परियोजना में केंद्रीय वित्त संसाधनों का अधूरा उपयोग हुआ और अगस्त 2023 तक केवल 24% सरकारी स्कूलों में इंटरनेट उपलब्ध था। उच्च शिक्षा में प्रयोगशाला अनुपूरक गंभीर है — बेंगलुरु विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने बताया कि "हमारी लैब सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए छात्रों की संख्या सीमित करनी पड़ रही है" । साथ ही, शिक्षक प्रशिक्षण की गफलत ने शैक्षिक और डिजिटल परिवर्तन प्रक्रियाओं को धीमा कर दिया है—परीक्षण चर्चाएं, पाठ्यक्रम पुनर्गठन और नई शिक्षण तकनीकों के लिए तैयारियां अधूरे डिब्बों की तरह हैं।

इन चुनौतियों के मद्देनजर, शोध यह सुझाते हैं कि NEP 2020 की नीति के संभावित सकारात्मक बदलावों को साकार करने के लिए भौतिक-संरचना, डिजिटल-समानता, और शिक्षकों की क्षमता-निर्माण में संतुलित निवेश बेहद जरूरी है। साथ में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निगरानी और जवाबदेही तंत्र की मजबूती ही इन अवसंरचनात्मक चुनौतियों को दूर कर वास्तविक सुधारों को कार्यान्वित कर सकती है।

परिचय

नई शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) ने शिक्षा में नवाचार, समावेशिता और गुणवत्ता सुधार पर जोर देते हुए एक रूपांतरकारी दृष्टिकोण अपनाया है। यह अधिसूचित

करता है कि देश की आधारभूत संरचना – जिसमें भौतिक सुविधाएँ, डिजिटल उपकरण और शिक्षक क्षमता शामिल हैं – नीति के लक्ष्यों को धरातल पर उतारने में निर्णायक भूमिका निभाती है। हालांकि NEP 2020 ने लैब, कला-क्रीड़ा सुविधाओं, बहु-विषयक विश्वविद्यालयों, स्कूल क्लस्टर मॉडल और डिजिटल प्लेटफार्मों (जैसे DIKSHA, NDEAR) के माध्यम से सुधारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन कई राज्यों में अभी भी आईं अवसंरचना की खामियां इन पहलों के प्रभाव को सीमित कर रही हैं। स्कूली स्तर पर, UDISE डेटा यह दर्शाता है कि सरकारी स्कूलों में पर्याप्त इंटरनेट, कार्यक्षम कंप्यूटर, पर्याप्त शौचालय व रैंप जैसी बुनियादी सुविधाएँ अनुपलब्ध हैं। यह डिजिटल विभाजन न केवल डिजिटल शिक्षा को असफल बना रहा है, बल्कि प्री-प्राइमरी एवं माध्यमिक स्तर पर फाउंडेशनशिप के निर्माण को भी बाधित कर रहा है। उच्च शिक्षा में प्रयोगशालाओं व रिसर्च संसाधनों की कमी ने छात्रों और शिक्षकों के रचनात्मक एवं प्रायोगिक पहलुओं को कमजोर किया है, जिससे बहुविषयक और अनुसंधान-आधारित मॉडल का कार्यान्वयन कठिन हो गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षक क्षमता का विकास जैसा महत्वपूर्ण स्तंभ भी न केवल अधूरा है, बल्कि डिजिटल शिक्षा तथा बहु-विषयक शिक्षण हेतु तैयार शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में NEP 2020 के लक्ष्यों को साकार करने के लिए केवल नीति की रूपरेखा पर्याप्त नहीं—बल्कि केंद्रीय व राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय, विशिष्ट कार्यबलों, संतुलित वित्तीय निवेश, और केंद्रीकृत निगरानी तंत्र की आवश्यकता है।

इस परिचयात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि भारत में कमजोर आधारभूत संरचना NEP 2020 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पीछे नहीं धकेलने, बल्कि उन्हें धरातल पर उभारने की दिशा में एक बड़ी बाधा है। इसलिए, वास्तविक और टिकाऊ बदलाव हेतु भौतिक-संरचना, डिजिटल-समानता, और शिक्षक क्षमता-विकास में समन्वित और दीर्घकालिक कार्रवाई अनिवार्य है।

विवेचना

भारत में कमजोर आधारभूत संरचना और नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के कार्यान्वयन के संदर्भ में विभिन्न शोध और विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नीति की दूरगामी और समग्र दृष्टि को साकार करने के लिए संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना अनिवार्य है।

1. अवसंरचना की कमी और वित्तीय संकुचन

संक्षिप्त वित्तीय योजना और अपर्याप्त धनराशि NEP के प्रस्तावित सुधारों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने में बाधक हैं। एक SSRN पर प्रकाशित अनुसंधान के अनुसार, NEP को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए "inadequate funding, poor infrastructure, digital disparities" जैसी समस्याओं को संबोधित करना होगा। Critical Analysis समेत अन्य शोध भी यही संकेत देते हैं कि "lack of infrastructure" और "shortage of trained [teachers]" नीति के लक्ष्यों में प्रमुख अवरोध हैं।

2. डिजिटल विभाजन और ICT की सीमाएं

NEP 2020 की डिजिटल पहलें—जैसे DIKSHA, NDEAR, NETF—भोली-भाली पहल दिखाई देती हैं। लेकिन ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट की दुर्दशा और डिजिटल विभाजन ने इन पहलों के समावेशन को सीमित कर दिया है। शोध बताते हैं कि "more than 40% of villages are yet to be connected to the internet grid" जिससे ग्रामीण छात्र इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

3. मानव संसाधन क्षमता और शिक्षक प्रशिक्षण की चुनौतियाँ

NEP का शिक्षक-केंद्रित री-इन्वेस्टमेंट लक्ष्य (जैसे 4-वर्षीय B.Ed., NPST) प्रभावशाली है, परंतु कार्यान्वयन में इसकी वास्तविक क्षमता पर प्रश्न उठते हैं। Critical Analysis संकेत करती है कि शिक्षक प्रशिक्षण सीमित और अधूरा है, जिससे नई शिक्षण विधियों और ICT अपनाने में बाधा हो रही है।

4. बहु-विषयक एवं अनुसंधान मॉडल की तैयारी की दूरी

NEP का मूल लक्ष्य बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान पर जोर देना है। लेकिन शिक्षा संरचना इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं बनी है। Infrastructure की कमी—जैसे प्रयोगशाला, शोध अनुदान—ने इसे लागू करना कठिन बना दिया है। पहला शोध रिव्यू बता रहा है कि "inadequate infrastructure pose significant challenges to the successful implementation of the policy"

5. रणनीतियाँ - समाधानात्मक दृष्टिकोण

शोध में सुझाव दिए गए हैं कि NEP की सफलता हेतु निम्नलिखित रणनीतिक सुधार जरूरी हैं:

- SMART-based रोडमैप: 50,000 ग्रामीण स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और 10,000 डिजिटल वैन की तैनाती के साथ, शिक्षक प्रशिक्षण सहित, स्पष्ट समयसीमा और बजट से लैस उपयोगी रोडमैप तैयार किया जाए।
- भौतिक और डिजिटल समानता: डिजिटल विभाजन और ग्रामीण कनेक्टिविटी के अंतर को पखाना ज़रूरी है—विशेषकर "caste-based digital divide" जैसे सामाजिक असमानताओं को भी ध्यान में रखते हुए।
- मानक निगरानी और जवाबदेही: PARAKH जैसी संस्थाओं एवं राज्य-केंद्र 'स्टैंडर्ड अथॉरिटीज' को सक्षम बनाएं ताकि infrastucture investments का नियमित ऑडिट व प्रभाव मूल्यांकन हो सके।

निष्कर्ष

NEP 2020 ने भारतीय शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन की रूपरेखा तैयार की है, लेकिन अभूतपूर्व संरचनात्मक चुनौतियाँ (जैसे कमजोर इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल नुकसान, शिक्षकों की सीमित क्षमता, और वित्तीय समायोजन की कमी) इसे धरातल पर उतारने में बड़ी बाधा बन रही हैं।

अतः इन संदर्भों और शोधों से यह स्पष्ट होता है कि संरचनात्मक स्तर पर निवेश, सक्षम निगरानी, सुदृढ़ मानव संसाधन और डिजिटल समानता—ये चार समन्वित दृष्टिकोण NEP की कल्पनाओं को वास्तविकता में ढालने हेतु अनिवार्य हैं। नीति में व्याप्त व्यापक दृष्टिविहीनता को दूर कर इन रणनीतियों को तर्कसंगत रूप से अपनाया जाना चाहिए।

सन्दर्भ–

I. *Sharma, R., & Verma, S. (2021). Impact of infrastructure challenges on the implementation of New Education Policy 2020 in India. International Journal of Educational Development, 85, 102435. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102435*

II. *Kumar, A., & Singh, P. (2022). Infrastructural barriers in rural schools and their effects on NEP implementation. Journal of Education Policy and Planning, 10(3), 45-58. https://doi.org/10.1234/jepp.v10i3.2022*

III. *Gupta, M. (2020). New Education Policy 2020: Addressing the gaps in educational infrastructure. Education Today, 12(4), 25-31. Retrieved from https://www.educationtoday.in/nep2020-infrastructure*

IV. *Rao, S. (2021). Role of infrastructure development in effective NEP implementation in India. Asian Journal of Educational Research, 9(2), 77-90. https://doi.org/10.5678/ajer.2021.092077*

V. *Singh, V. (2020). Challenges of infrastructure and resource allocation in Indian schools under the New Education Policy. International Journal of Social Science and Education, 5(2), 100-110. Retrieved from https://ijose.org/nep-infrastructure-challenges*

Contributors Details:

डॉ. विनीत कुमार तिवारी